

तुरन्त बन्द होनी चाहिए। पेड़ों के विनाश से इस क्षेत्र में वन्य पशु-पक्षी, प्राकृतिक सुषमा, जलवायु आदि भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार द्वारा इस ओर ध्यान देकर पुर्णिया जिले और बिहार में पर्यावरण समुन्नत करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

(iii) Shortage of Application Forms with the Union Public Service Commission

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग के मुख्यालय में आवेदन-पत्रों (एप्लीकेशन फार्म्स) की इस कदर कमी हो गई है कि पिछले दो सप्ताह से आयोग ने दिल्ली के बाहर फार्म भेजना बन्द कर दिया है, जबकि विभिन्न पदों के लिए छः हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र मंगवाए हुए हैं। यह स्थिति अभी कुछ दिन और बने रहने की आशंका है। केन्द्र व राज्यों के हजारों सरकारी पदों के लिए नियुक्तियां करने वाले इस आयोग के पास आवेदन-पत्रों की कमी का मामला इसलिए और भी संगीन हो गया है कि आयोग ने कुछ ही समय पूर्व लाखों रुपये की लागत से अपना आफसेट छापाखाना लगाया है। दिल-चस्पी की बात यह भी है कि पिछले दो ड़ाई महीनों से आवेदन पत्रों की कमी होने के बावजूद अपने छापाखाने का इस्तेमाल आयोग ने तब तक नहीं किया जब तक आवेदन पत्रों का स्टॉक एक-दम खत्म नहीं हो गया। किसी तरह बाजार से आफसेट प्लेट बनवाकर तथा अपने छापाखाने में ओवरटाइम काम करवा कर आयोग ने चार-पांच हजार फार्म छपवा लिए हैं। अधिकारियों ने दिल्ली से बाहर डाक से फार्म भेजने की मनाही कर दी है और यूपी एससी भवन के काउन्टर पर एक व्यक्ति को एक ही फार्म देने का आदेश लागू कर दिया है। इस प्रकार दिल्ली में रह रहे व्यक्ति को तो फार्म उपलब्ध है, किन्तु दिल्ली से बाहर के किसी भी व्यक्ति को फार्म नहीं भेजे जा रहे। इस प्रकार दिल्ली से बाहर के कितने प्रत्याशी कितनी परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों के अवसर खो बैठेंगे, इसका ठीक-ठाक

अन्दाजा लगाना कठिन है। लेकिन आयोग के सूत्रों के अनुमान के मुताबिक ऐसे प्रत्याशियों की संख्या हजारों में होगी।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की गंभीरता को समझते हुए संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को निर्देश देकर शीघ्र से शीघ्र आवेदन पत्रों में इस अभाव को समाप्त करायें।

(iv) Need for arresting the declining trend in export of canned fruit products to USSR

SHRI S.T.K. JAKKAYAN (Periyakulam) : The U.S.S.R. has been the traditional importer of Indian canned products like juices, jam, pulp, etc. from the annual average of 8,000 to 10,000 tonnes, this reached 47,000 tonnes in 1982 and the value was about Rs. 38 crores. But unfortunately in 1982 a disturbing trend started in the sense that the USSR started making claims against Indian suppliers on an average of 10% to 12% on the grounds of defective packaging, denting of cans, etc., though the Indian suppliers did not receive any such claims from other countries to whom they have exported processed fruit products.

In 1983, the USSR buyers have slashed their purchases to 28,000 tonnes valued at approximately Rs. 22 crores. Even here, they have been shifting their grounds in respect of shipments. First, they wanted the shipments to be effected only after July, which has been postponed to September, 1983. Suddenly, now it is reported that they want indefinite postponement. Any further postponement of shipment means decimation of this industry as a whole because the products are perishable. Secondly, the subsidiary industries engaged in can-making and such other inputs would also be closed.

It is suggested that the Government should try to arrest this destabilising trend by immediately initiating mutual discussions for arriving at an agreed solution, so that the situation within the country is not further aggravated.